

दैनिक

रोकथोक लेखनी

(R)

महाराष्ट्र में 50-50 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी महायुति, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव



Page - 4

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

खतरनाक इमारत में अभी भी रहते हैं 175 परिवार

महायुति कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री की अपील लापरवाह मत बनो, सवालों के जवाब दो!

मुंबई: इस साल, दक्षिण मुंबई में सेस्ट इमारतों में से 20 को उच्च जोखिम वाली इमारतों की सूची में शामिल किया गया है। इस बिल्डिंग के 412 घरों को खाली करने की चुनौती म्हाडा की मुंबई बिल्डिंग मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड के सामने था। इसके मुताबिक, 412 में से 200 से ज्यादा मकान खाली करा लिए गए हैं। हालांकि, 176 परिवार अभी भी खतरनाक इमारतों में रह रहे हैं और सुधार बोर्ड द्वारा इन परिवारों को जल्द से जल्द पारगमन शिविरों या अन्यत्र स्थानांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ने अपने घर खाली कर दिए हैं और 176 लोगों ने अभी तक अपने घर खाली नहीं किए हैं, सुधार बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया। यानी 176 परिवार अभी भी खतरनाक इमारतों में रह रहे हैं और इमारतों को जल्द से जल्द ट्रांजिशन कैम्प या अन्य जगहों पर ले जाकर खाली करना

412 में से 200 से ज्यादा मकान खाली करा लिए गए

अपना घर खाली नहीं करेंगे, उन्हें पुलिस बल का प्रयोग कर बेदखल करने की सोच रहे हैं।

एमएचडी से इमारतें खाली करने या ट्रांजिट कैम्प में जाने के बाद हम अपने असली घर में कब लौटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इमारत का पुनर्विकास किया जाएगा या नहीं। सालों तक ट्रांजिट कैम्प में रहना पड़ता है। इसलिए, निवासी अपने घर खाली करने के खिलाफ हैं। वहीं, सुधार बोर्ड के संक्रमण शिविर अक्सर निवासियों की मूल इमारतों से बहुत दूर होते हैं। इस तथ्य के बावजूद दक्षिण मुंबई में उपनगरों में बड़ी संख्या में पारगमन शिविर निर्माणाधीन हैं, निवासियों को अपने घर खाली करने से इनकार करते देखा जाता है। यह तस्वीर हर साल आयोजित की जाती है और सुधार बोर्ड को इमारतों को खाली कराने के लिए पुलिस बल का उपयोग करना पड़ता है।

जरूरी है। इस बीच, पिछले सप्ताह सुधार बोर्ड के मुख्य अधिकारी समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने इन इमारतों का निरीक्षण किया और निवासियों से बातचीत की। उन्हें मकान खाली करने का निर्देश दिया गया। सुधार बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि इस अधिसूचना के बाद जो निवासी अगले कुछ दिनों में



बोर्ड को 412 आवासीय ब्लॉकों के परिवारों को संक्रमण शिविर में स्थानांतरित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। सूची प्रकाशित होने के बाद, कुछ परिवार पारगमन शिविरों या अन्यत्र चले गए। मकान खाली नहीं करने वाले 258 परिवारों को सुधार बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया है।

इस नोटिस के बाद, 82 परिवारों

इमारतें जर्जर हैं और सभी 14 हजार इमारतें खतरनाक हैं। ऐसे में बरसात के दौरान ये इमारतें ढह जाती हैं। इसलिए हर साल इन इमारतों का सर्वेक्षण किया जाता है और खतरनाक इमारतों की सूची प्रकाशित की जाती है। इस बिल्डिंग में मॉनसून से पहले घर खाली करा लिए जाते हैं। इसके मुताबिक, इस साल 20 इमारतें बेहद खतरनाक इमारतों की सूची में शामिल हैं। इन 20 इमारतों में कुल 711 इकाइयाँ हैं जिनमें से 494 आवासीय और 217 गैर-आवासीय हैं। इन आवासीय स्लम परिवारों में से 36 ने पहले से ही अपने आश्रय के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। 46 परिवारों को म्हाडा से ट्रांजिट कैम्प में स्थानांतरित किया गया। इसलिए, सूची के प्रकाशन के बाद, सुधार

मुंबई: विवेक विचार मंच द्वारा यशवंतराव चव्हाण हॉल में आयोजित चौथे राज्य स्तरीय सामाजिक न्याय सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिंदे बोल रहे थे। कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, कौशल विकास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना,



महानिदेशक

डॉ. सुनील

वारे, विवेक विचार मंच के अध्यक्ष प्रदीप रावत, पदाधिकारी महेश पोहनेरकर सहित प्रदेश के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

हालांकि राज्य में कुछ एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनजीओ विकास के विरोधी हैं। विपक्ष और इन संगठनों ने पूरे राज्य में गांव-गांव जाकर झूठी कहानियाँ फैलाईं। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें कम हो गईं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे अब लापरवाही न बरतें।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के साथ-साथ रैयतों का राज्य लाने का काम भी किया। उनके आदर्श को आंखों के सामने रखते हुए राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज एवं भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कार्य निरंतर जारी रखा। राज्य सरकार इसी विचार को आगे बढ़ा रही है और समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों के माध्यम से पिछड़े वर्ग के तत्वों को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है। शिंदे ने कहा कि सभी को काम उपलब्ध कराने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

डेवलपर्स की उदासीनता को महारेरा ने गंभीरता से लिया

अब तक केवल 195 परियोजनाओं में 'शिकायत निवारण कक्ष'

मुंबई: महारेरा ने पिछले साल अगस्त में आदेश दिया था कि सभी डेवलपर्स को घर खरीदारों की शिकायतों के समाधान के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करना चाहिए। इसकी समीक्षा करने के बाद पाया गया कि राज्य में केवल 195 परियोजनाओं ने ही ऐसे कमरे स्थापित किये हैं और आवश्यक विवरण वेबसाइट पर दर्ज किया है। महारेरा ने डेवलपर्स की इस उदासीनता को गंभीरता से लिया है और महारेरा डेवलपर्स के लिए



हर परियोजना के लिए एक ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास करने जा रहा है। प्रारंभ में, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग प्रणाली घर खरीदते या पंजीकृत करते समय ग्राहक के संपर्क में रहती है। कई परियोजनाएं यह निर्दिष्ट नहीं करती कि कोई

शिकायत या समस्या होने पर बाद में किससे संपर्क करना है। ऐसे में ग्राहक को पता नहीं होता कि शिकायत कहाँ करें। अक्सर आधिकारिक विश्वसनीय जानकारी के अभाव में गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं और शिकायतें बढ़ जाती हैं।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता इकाई की लंबित फाइलों को मंजूरी के बावजूद

मरीजों को सहायता प्राप्त करने में दिक्कत!

मुंबई: मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता इकाई की लंबित फाइलों को पिछले हफ्ते मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन मरीजों को वास्तविक सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल सपोर्ट रूम पर आचार संहिता लागू नहीं होने के बावजूद फाइलें अटकी हुई हैं। हालांकि इन फाइलों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कई मरीजों को अस्पताल से घर भेज दिया गया है, जिससे सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। हालांकि कुछ रोगियों ने अग्रिम भुगतान कर दिया है, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता केंद्र से सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

लोकसभा चुनाव के दौरान मेडिकल वार्ड से जुड़ी करीब 1800 फाइलें रुकी हुई थीं। यह



फाइल पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सौंपी थी। हालांकि, फाइलें स्वीकृत होने के बावजूद, चिकित्सा सहायता प्रदान करने की शर्तों के कारण, रोगियों को अब वास्तव में सहायता प्राप्त करने में

कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कि इन फाइलों के कारण रुकी हुई

चिकित्सा सहायता तत्काल उपलब्ध करायी जाये, कई मरीजों के परिजन अनुभव कर रहे हैं कि मेडिकल वार्ड में अधिकारियों द्वारा तरह-तरह के सवाल उठा कर सहायता रोकी जा रही है। चिकित्सा सहायता पर

लोकसभा की आचार संहिता लागू नहीं होने के बावजूद फाइलों पर हस्ताक्षर न होने से इन मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी है।

इस बारे में पूछे जाने पर चिकित्सा विभाग के प्रमुख और मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे ने स्वीकार किया कि पिछले सप्ताह यही मामला था। लेकिन अब करीब 170 फाइलों को ही मंजूरी का इंतजार है। इसी सप्ताह मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सहायता से जुड़ी फाइलों का तत्काल निस्तारण किया। इससे इन मरीजों को चिकित्सीय सहायता भी मिलनी शुरू हो गयी है। चिवटे ने यह भी कहा कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा।



संपादकीय...



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

एक राष्ट्र-एक चुनाव

देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर कुछ दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक ने इस बहस को नए सिरे से छेड़ दिया है। बैठक में इस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा जरूर हुई, लेकिन विमर्श और आम सहमति की राह बनती नहीं दिखी। इसे लेकर विपक्ष भी दोफाड़ दिखा। कांग्रेस, सपा, बसपा और डीएमके समेत 16 दलों का बैठक से दूर रहना इस मुद्दे को पूर्णतया खारिज करने जैसा है, जबकि बैठक में शामिल एनडीए के

घटक दलों समेत 21 दलों का समर्थन इस विचार को तेज गति प्रदान करने की पहली सफल कोशिश है। सीपीआइ और सीपीएम ने इसके क्रियान्वयन को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन वैचारिक रूप से ये एक साथ चुनाव के समर्थन में हैं। देश के किसी भी मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बहस लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इतने महत्वपूर्ण विषय पर आहूत किसी बैठक से कुछ दलों का दूरी बना लेना लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना है। 'पंचायत से पार्लियामेंट तक' के चुनावों को एक साथ कराए जाने के विचार को किसी पार्टी की पहल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया है। यह रिपोर्ट इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनावों को भी एक साथ कराने की वकालत करती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय विधि आयोग के समक्ष सरकार के इन विधायी प्रयासों का समर्थन किया था। 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' अवधारणा भारत में संसदीय, राज्य और स्थानीय सहित सभी चुनावों को एक निश्चित अंतराल, आमतौर पर हर पांच साल में आयोजित करने की वकालत करती है। भारतीय राजनीति में एक साथ चुनाव कराने का यह विचार नया नहीं है। इससे पहले 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने की वजह से पहली बार एक साथ चुनाव होने का चक्र बाधित हुआ था। वहीं चौथी लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई थी, जिसकी वजह से 1971 में नए चुनाव हुए। एक साथ चुनाव का विचार पहली बार औपचारिक रूप से भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी 1983 की रिपोर्ट में प्रस्तावित किया था। बाद में भारत के विधि आयोग ने भी इसका समर्थन किया। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार को अमल में लाना देशहित में है। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष की चिंता है कि मौजूदा सरकार अपने प्रभाव और महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के जरिये लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को प्रभावित करने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में स्थानीय मुद्दे गौण हो सकते हैं, लेकिन यह भय व्यर्थ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन उसके तुरंत बाद कई विधानसभा चुनावों में उसे पराजय मिली। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में भाजपा को सात सीटों पर मिली बढ़त और विधानसभा में बीजद को बहुमत मिलना भी यही जाहिर करता है। दरअसल देश और प्रदेशों के अपने-अपने मुद्दे संबंधित चुनावों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह राशि किसी दल की नहीं, बल्कि भारत सरकार के कोष में संचित देश के करदाताओं की है।

छात्राओं को मिलेगी मुफ्त उच्च शिक्षा



मुंबई। छात्राओं के लिए एक खुशी की खबर है। राज्य की छात्राओं को अब मुफ्त उच्च शिक्षा मिलेगी और इसका जीआर 27 तारीख से निकाला जायेगा। इसकी जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दी है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आश्वासन दिया था कि लड़कियों को इस

शैक्षणिक वर्ष से मुफ्त उच्च शिक्षा दी जाएगी। लेकिन शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद भी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का लाभ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण निःशुल्क शिक्षा का जीआर जारी नहीं हो सका। अब यह जीआर 27 तारीख से निकाला जायेगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत

पाटिल ने आश्वासन दिया था कि लड़कियों को इस शैक्षणिक वर्ष से मुफ्त उच्च शिक्षा दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से लड़कियों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा

लेकिन शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद भी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का लाभ नहीं मिला। नए शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लेने के दौरान छात्राओं को बताया गया कि संस्थान प्रबंधन की ओर से हमारे पास शासनादेश नहीं आया है। लड़कियों को मुफ्त

क्या हैं शर्तें, जानिए विस्तार से

निःशुल्क शिक्षा के लिए माता-पिता की वार्षिक आय आठ लाख तक होनी चाहिए। राज्य सरकार कला-विज्ञान-वाणिज्य के साथ-साथ चिकित्सा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्रों की 100 प्रतिशत फीस वापस करेगी। इससे प्रदेश की 20 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ होगा।

की गई थी। यह घोषणा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने 9 फरवरी, 2024 को जलगांव में की थी। यह भी कहा गया कि 8 जून से मुफ्त शिक्षा लागू कर दी जाएगी।

शिक्षा देने का आदेश होगा तो उसे तुरंत लागू किया जाएगा। उस समय छात्रों और अभिभावकों की मांग थी कि राज्य सरकार तुरंत लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का आदेश जारी करे।

सेक्स रैकेट का पदार्फाश दो महिलाओं को पुलिस ने कराया मुक्त



नालासोपारा : नालासोपारा पूर्व में फायर ब्रिगेड के पास, गैलेक्सी होटल के बाहर, अवैध वेश्यावृत्ति में लिप्त एक पुरुष दलाल को गिरफ्तार करने के बाद दो पीड़ित महिलाओं को छुड़ाने में पुलिस की अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम टीम, नालासोपारा को सफलता मिली है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि, वसंत नगरी नालासोपारा पूर्व से एक पुरुष वेश्यादलाल, वेश्यावृत्ति के लिए नालासोपारा पश्चिम के गैलेक्सी होटल के बगल में लड़कियां मुहैया कराएगा। ऐसी गुप्त जानकारी पुलिस निरीक्षक सौरभ

पवार को मिली। इसके बाद फर्जी ग्राहक और दो पंच भी उक्त स्थान पर गये। जहां छापेमारी करके एक 30 वर्षीय दलाल को गिरफ्तार करके दो पीड़ित महिलाओं को छुड़या है। अधिकारी ने बताया कि, अभियुक्त पीड़ित महिलाओं को पैसों का लालच देकर, अलग-अलग ग्राहकों को बुलाकर उनसे पैसे लेता था और पीड़ित महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल देता था और वेश्यावृत्ति के लिए भुगतान और कमीशन प्राप्त करने के बाद, वह एक महिला से कुल 3500 रुपये लेता था और पीड़ित महिलाओं 500 रुपये देता था। अभियुक्त के ऊपर आचोले पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

बुजुर्ग कारोबारी से 20 लाख की ठगी



ठाणे। ठाणे में बुजुर्ग कारोबारी से 20 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि पुलिस ने 69 साल के व्यवसायी से गेम जोन में बच्चों के लिए मशीनों की आपूर्ति के नाम पर 20 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी की ये घटना नवंबर 2022 और 2024 के बीच हुई थी। व्यवसायी वीरधवल घाग द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पुलिस ने गुरुवार को एक फर्म चलाने वाले आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के

तहत मामला दर्ज किया। नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा, 'शिकायतकर्ता ने बच्चों के खेल क्षेत्र के लिए 22 लाख रुपये की कुछ मशीनों का ऑर्डर दिया था लेकिन आरोपी द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री पुरानी थी और उनसे पैसे नई मशीनों के वसूल लिए गए थे। अभी एक हफ्ते पहले ही ठाणे में ठगी का एक और मामला सामने आया था। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में प्लेट खरीदारों से 4 करोड़ की ठगी कर ली गई। इस मामले में पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने डेवलपर और एक सहकारी बैंक के पूर्व सीनियर अफसर समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि फ्लैट देने के बहाने 18 लोगों से 4 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर ली।

बम धमाके का फर्जी मेल चेन्नई से भेजा गया था

मुंबई। सहरा पुलिस ने बम धमाके का फर्जी मेल करनेवाले शख्स के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी के मेल करने के ठिकाने का पता लगा लिया है। पुलिस की टीम आरोपी को ढूँढने के लिए चेन्नई पहुंच गई है।

सहरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के मेल आईडी पर एक मेल प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि "नमस्ते, हवाई अड्डे पर विस्फोटक छिपे हुए हैं। बम जल्द ही फूटेंगे, आप सब मरेंगे। इस हत्याकांड के पीछे केएनआर ग्रुप का हाथ है। 1 मई, को दिल्ली में हुए स्कूल पर



हमले में भी केएनआर का हाथ है। जिसका अलर्ट सुरक्षा एजेंसी को दिया गया।

यह मेल 18 जून 2024 को मेल आईडी पर प्राप्त हुआ था। जिसके बाद सिक्स्युरिटी चेक में पता चला कि ऐसा कुछ भी हवाई अड्डे पर नहीं है। जिसके बाद 19 जून को हुई मीटिंग में

शिकायत दर्ज करवाने के बारे में तय किया गया। इसीमें संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के बारे में निर्णय लिया गया। जिसके बाद सुरक्षा अधिकारी ने मामले में एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर में कहा गया है कि जाव वे ड्यूटी पर तैनात थे तब लोगों के फीड बैक के लिए उपलब्ध कराई गई ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा गया था। जिसके बाद सहरा पुलिस ने आईपीसी की धारा 505 (1) (ब) और 506 (2) के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। पयलिस चेन्नई तक पहुंच तो गई है लेकिन अभी आरोपी उनके पकड़ से बाहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

editor@roktoklekhani.com

+91 99877 75650

Faisal Shaikh @faisalroktok



Watch Us On YouTube LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE youtube@roktoklekhani



ऑटो चालकों ने किया हड़ताल का ऐलान !



मुंबई : केन्द्रीय परिवहन विभाग ने राज्य सरकार को वाहन पात्रता प्रमाणपत्र के नवीनीकरण में देरी की स्थिति में विलंब शुल्क लगाने का निर्देश दिया है। सरकार के फैसले के खिलाफ अब राज्य के रिक्शा चालकों ने आक्रामक रुख अपना लिया है और कल, सोमवार को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

मुंबई सहित राज्य में लगभग 1.5 लाख रिक्शा चालक-मालिक स्व-रोजगार हैं। राज्य सरकार रिक्शा किराया दरें, रिक्शा संचालन से

संबंधित सभी नियम और शर्तें तय करती है। कोरोना काल में सरकार ने 1500 रुपये के अलावा कोई मदद नहीं की।

कोरोना के बाद रिक्शा चालकों को काफी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। इसी तरह वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख से 50 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क लिया जा रहा है। इसके चलते रिक्शा चालक-मालिक संघ ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेतृत्व में कल सोमवार को राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है।

बीएमसी ने अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने के लिए मांगी पुलिस सुरक्षा

मुंबई : बीएमसी ने लोअर परेल स्थित कमला मिल्स में किए गए अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी है। मार्च में, नगर निकाय ने मनोरंजन स्थल से पार्किंग स्थल में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए नोटिस देने के बाद उसी परिसर में अनधिकृत निर्माण के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। यह कार्रवाई कार्यकर्ता-वकील और पूर्व डाक सेवा अधिकारी आभा सिंह द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद की गई थी, जिसमें कहा गया था कि स्वीकृत योजना में मनोरंजन स्थल के रूप में दर्शाई गई 3,719 वर्गमीटर भूमि को बिना अनुमति के पार्किंग स्थल में बदल दिया गया था। कई स्थानों पर हल्की से बारिश



पिछले साल जुलाई में सिंह द्वारा दायर की गई शिकायत में कहा गया था कि भूमि को तत्कालीन विकास नियंत्रण विनियमन 23 (1) (एफ) और विनियमन 27 (1) (एफ) विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियमन, 2034 के अब अनुरूप प्रावधानों के तहत एक बगीचे के रूप में विकसित किया जाना चाहिए था। इसमें यह भी

उल्लेख किया गया था कि मनोरंजन स्थल पर बड़े जनरेटर रखे गए थे और कारों की पार्किंग की सुविधा के लिए भूमि को कंक्रीट से पक्का किया गया था। 'पिछली बार की गई कार्रवाई आंशिक थी और यह सिर्फ दिखावा था। सिंह ने कहा, 'अगर किसी मनोरंजन मैदान को पे-एंड-पार्क में बदल दिया जाता है, तो यह

वैधानिक विकास नियंत्रण नियमों का घोर उल्लंघन है।' 'लोअर परेल एक अत्यधिक प्रदूषित जगह है, जहाँ पेड़ों की सख्त जरूरत है। मुंबई के तेजी से बिगड़ते पर्यावरण को देखते हुए, मनोरंजन मैदान को बहाल करने और वहाँ पौधारोपण करने में नगर निगम की देरी शहर के नाजुक पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होगी। अ' २३३ पीं - टै' २३३ प्रल्लः ठाणे और मुंबई के इलाकों में येलो अलर्ट जारी पेड़ों की कमी के कारण मुंबई की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है और चालाक बिल्डरों ने मनोरंजन मैदानों पर कब्जा कर लिया है। हर मुंबईकर का कर्तव्य है कि वह हमारे खुले स्थानों और पेड़ों पर नजर रखे।'

मुंबई-बनारस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन छह माह बढ़ा

मुंबई : बनारस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन रेलवे ने छह माह के लिए बढ़ा दिया है। अब 27 दिसंबर तक ट्रेन का संचालन वाया मैनपुरी होगा। इससे यात्रियों को बनारस और मुंबई आने-जाने में राहत बनी रहेगी। पहले 1 जुलाई तक ही ट्रेन का संचालन किए जाने का आदेश था।



यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने मुंबई-बनारस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया था। पहले इस ट्रेन का संचालन एक जुलाई तक ही करने के आदेश दिए गए थे। इसके कारण बनारस और मुंबई आने-जाने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन रेलवे ने उनके लिए ट्रेन का संचालन आगे बढ़ा दिया है। मुंबई से बनारस जाने वाली गाड़ी संख्या 09183 का संचालन बढ़ाकर

25 दिसंबर तक और बनारस से मुंबई जाने वाली गाड़ी संख्या 09184 का संचालन 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व की भांति ही मैनपुरी और भोगांव दोनों स्टेशन पर ये ट्रेनों रुकेगीं। बनारस से चलकर मुंबई जाने वाली ट्रेन रात 21.05 मिनट पर और बनारस से मुंबई चलकर जाने वाली ट्रेन सुबह 4.10 बजे मैनपुरी पहुंचेगी।

50 हजार का इनामी चोर नायगांव से गिरफ्तार

मुंबई : पुलिस ने नायगांव से 50,000 रुपये के इनामी उत्तर प्रदेश के एक चोर को गिरफ्तार किया है। रहिमउल्ला अंसारी (32) और उसके साथी उपेंद्र सोनी, रोहित पांडे और शेखर मिश्रा यूपी में खड़ी कारों में चोरी करते थे। जब उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो मास्टरमाईड अंसारी फरार हो गया। नायगांव क्राइम यूनिट को हाल ही में उनके यूपी समकक्षों ने सूचित किया था कि अंसारी वसई के कमान इलाके में रह रहा है। नायगांव और यूपी की पुलिस टीमों ने उसका पता लगाया और उसे धर दबोचा। पुलिस ने कहा कि अंसारी ने वसई क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों में भी चोरी की। रोहित



यादव ने कथित तौर पर वसई की सड़क पर आरती यादव की हत्या कर दी, जो उसके सेलफोन तोड़ने के एक पिछले गैर-संज्ञेय अपराध से चिह्नित एक अशांत रिश्ते के बाद हुई थी। भोईवाड़ा पुलिस ने मुंबई के अस्पतालों से लैपटॉप चुराने वाले 34 वर्षीय एक व्यक्ति का पता

लागाया और उसे 5.10 लाख रुपये के 11 लैपटॉप चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया। हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल में एक कर्मचारी का लैपटॉप ओपीडी रूम से गायब हो गया। हाई चार्जिंग स्पीड और बैटरी क्षमता वाले पावर बैंक चलते-फिरते कनेक्ट रहने के लिए जरूरी हैं।

ठाणे और मुंबई के इलाकों में येलो अलर्ट जारी

मुंबई : क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए ठाणे और मुंबई के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, ठाणे और मुंबई दोनों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तेज हवाएँ चलने के साथ गरज और भारी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा, विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए रायगढ़ और रत्नागिरी के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।



जलगांव, अमरावती, भंडारा और अन्य इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएँ चलने की संभावना है। इससे पहले, ठाणे के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण, फायर ब्रिगेड विभाग को बड़ी संख्या में बचाव कॉल का जवाब देना पड़ा। ये कॉल पेड़ गिरने, होर्डिंग की दीवार गिरने और आग लगने की चिंता में की गई थीं। शुक्रवार को ठाणे के एक फुटबॉल ग्राउंड में शोध गिरने से छह बच्चे घायल पाए गए।

दो भाइयों ने 60 महिलाओं से 2.4 करोड़ रुपये की ढगी की

मुंबई : मालवणी पुलिस ने दो भाइयों के खिलाफ 60 महिलाओं को सस्ते मकान का लालच देकर 2.4 करोड़ रुपए ठगने का मामला दर्ज किया है। आरोपी अविनाश देवराम भांजी और प्रमोद देवराम भांजी फिलहाल पुलिस की तलाश में हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उन्होंने इसी तरह के अन्य अपराध किए हैं। पुलिस के अनुसार, मलाड मध्य क्षेत्र की स्थानीय महिलाओं ने एक महिला समूह बनाया, जिसने कई वर्षों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। आठ साल पहले, संगठन की सदस्य साधना भंडारे को एक परिचित के माध्यम से भांजी भाइयों से मिलवाया गया। भाइयों ने संगठन की सभी महिलाओं को सस्ते मकान देने का वादा करते हुए किफायती



आवास की एक योजना पेश की। उन्होंने महिलाओं को मलाड के मध्य, शिवाजीनगर, गेट 3 में एक स्थान दिखाया और उन्हें अपनी योजना में मकान के लिए आवेदन करने के लिए राजी किया। साठ महिलाओं ने घर के लिए आवेदन किया, प्रत्येक ने 4 लाख रुपये का भुगतान किया, कुल मिलाकर 2.4 करोड़ रुपये। हालांकि, भाइयों ने तय समय के भीतर वादा किए गए घरों का निर्माण करने में विफल रहे और पैसे वापस नहीं किए। उन्होंने कथित तौर पर महिलाओं को धोखा देने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।

जब धोखाधड़ी का पता चला, तो महिलाओं ने मालवणी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की पुष्टि करने के बाद, पुलिस ने 21 जून को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अविनाश और प्रमोद भानजी के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना), और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) शामिल हैं। शिकायत को वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है, जिन्होंने मालवणी पुलिस को आरोपी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

तालाब में दो बच्चे डूबे, एक की मौत और एक लापता

मुंबई : रायगढ़ जिले की अलीबाग तहसील के मनुवाली इलाके में स्थित एक तालाब में रविवार को दो बच्चे डूब गए। इनमें से एक बच्चे का शव पुलिस ने बरामद कर लिया, जबकि एक बच्चा लापता है। फायर ब्रिगेड के जवान और गांव वाले मिलकर लापता बच्चे की तलाश कर रहे हैं। अलीबाग तहसील के मनुवाली में स्थित तालाब में आज दोपहर अथर्व हाके और शुभम बाला नामक दो बच्चे तैरने गए थे। इन दोनों को पानी का अंदाजा नहीं था, इसी वजह से दोनों तालाब में डूब गए। फायर ब्रिगेड की टीम और जिले से बचाव दल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और अथर्व हाके का शव तालाब से निकाल लिया है।



पुणे में समय सीमा के बाद भी बेची जा रही थी शराब 8 गिरफ्तार, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड



पुणे: पुणे में तय समय सीमा के बाद भी एक बार में शराब बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ चार पुलिसकर्मीयों को भी सस्पेंड कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे शहर के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित एक बार का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें बार में कुछ

लोग नशीले पदार्थ के साथ दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, यह बार रविवार को सुबह पांच बजे तक खुला था और यहां तय समय सीमा के बाद भी शराब बेची जा रही थी। पुणे में बार और पब को रात डेढ़ बजे तक खुले रहने की अनुमति है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से 'पीटीआई-भाषा'

को बताया, "हमने लिक्विड लीजर लाउज (एल3) के मालिकों और कर्मचारियों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि यह प्रतिष्ठान रविवार को तय समय सीमा से अधिक देर तक खुला था।"

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, महाराष्ट्र निषेध अधिनियम और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में रात्रि ड्यूटी कर रहे शिवाजीनगर पुलिस थाने के एक निरीक्षक, एक सहायक निरीक्षक और दो बीट मार्शल को निलंबित कर दिया गया है।

नागपुर में कुएं में धक्का देकर युवक की हत्या, 2 महीने बाद पुलिस ने सुलझाई गुत्थी

नागपुर. नोगा फैक्ट्री के समीप 2 महीने पहले बोरियापुरा निवासी मोहम्मद फरहान उर्फ मोहम्मद नियाज (19) को कुएं में मृतावस्था में पाया गया था। पांचपावली पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था। आखिर पुलिस को एक टिप मिली और जांच में पता चला कि फरहान का योजनाबद्ध तरीके से अपहरण किया गया था। मारपीट करने के बाद उसे कुएं में धक्का देकर हत्या की गई। इस प्रकरण में अब पांचपावली पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया है।

आरोपियों में डोबीनगर, मोमिनपुरा निवासी लतीफ उर्फ हैदराबादी ताजुद्दीन शेख (20), मोहम्मद शाहिद उर्फ एमपीडीए मोहम्मद असलम (30), अब्दुल वसीम उर्फ वस्सी अब्दुल अजीज



(25), रेहान उर्फ मोटू मुक्का रियाज शेख (25), जुनैद मोहम्मद असलम (25) और मोतीबाग निवासी इरफान उर्फ गजनी रहमान खान (35) का समावेश है। पुलिस ने लतीफ हैदराबादी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शाहिद कपिलनगर थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में पहले से जेल में है। पुलिस के अनुसार, शाहिद एमपीडीए और फरहान के जुड़वा भाई अजमान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दिसंबर 2023 में अजमान और

उसके साथियों ने शाहिद एमपीडीए पर हमला कर उसके साथ मारपीट भी की थी। तब से शाहिद अजमान को सबक सिखाना चाहता था। **भाई गिरफ्त में और कर दिया गेम** घटना के 3 दिन पहले ही तहसील पुलिस ने अजमान को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया था। शाहिद और अन्य आरोपियों ने इसी बात का फायदा उठाया। 21 अप्रैल की रात 8:30 बजे के दौरान शाहिद और लतीफ ने बोरियापुरा के पास फरहान को रोका।

पुणे में मानवता हुई शर्मसार, पिता और चाचा ने की नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी, चचेरा भाई ने कई बार किया बलात्कार



पुणे: महाराष्ट्र के पुणे से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। शहर के हडपसर इलाके से 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ पिता, चाचा और चचेरे भाई ने कथित तौर पर यौन शोषण किया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद तिन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, नाबालिग की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि किशोरी ने स्कूल में एक सत्र के दौरान आपबीती सुनाई, जिसके बाद यह मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चचेरे भाई के चाचा के बाद लड़की के पिता ने भी कई बार उसका यौन शोषण किया।

रहती है। मां के शिकायत के अनुसार सबसे पहले पीड़िता के चचेरे भाई ने जुलाई 2023 में उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे जान गवांती पड़ेगी। पुलिस के एक अधिकारी ने आगे बताया कि उसके बाद जनवरी 2024 में उसके चाचा ने कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया था। यही नहीं, मां के गांव जाने के बाद मौके का फायदा उठाकर लड़की के पिता ना भी कई बार नाबालिग का यौन शोषण किया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग के पिता और चाचा 40 साल के हैं, जबकि चचेरे भाई की उम्र 20 साल है। तीनों को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

महाराष्ट्र में 50-50 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी महायुति, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव

मुंबई : महाराष्ट्र के विधान परिषद की 15 सीटों पर अगले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक चुनाव क्षेत्र से संबंधित 4 सीटों पर इसी 26 जून को मतदान होने हैं। वहीं अन्य 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान होगा। इस बीच, बताया जा रहा है कि 11 जुलाई को होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन वाली महायुति ने फीफ्टी-फीफ्टी का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। फॉर्मूला



के मुताबिक, 11 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी 6 सीटों पर महायुति में शामिल शिवसेना (शिदि गुट) और एनसीपी (अजीत

गुट) के उम्मीदवारों को उतारने की रणनीति बनाई गई है।

वोटों का समीकरण जानकारी के लिए बता दें कि विधान परिषद में एक सदस्य को

निर्वाचित होने के लिए औसतन 23 वोटों की जरूरत होती है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, उसके बाद एसीपी (अजीत पवार) के 40 और शिवसेना (शिदि गुट) के 38 विधायक हैं। वहीं, एमवीए में कांग्रेस के 37, शिवसेना (उद्धव गुट) के 15 और एनसीपी (शरद पवार) के 10 विधायक हैं, जबकि विधायक अशोक पवार और नवाब मलिक ने दोनों गुटों में से किसी को भी समर्थन देने का हलफनामा नहीं दिया है।

शर्मनाक ! शरुक्स ने प्रेमिका के 4 वर्षीय बेटे को ट्रेन में लावारिस छोड़ा, रचा अपहरण का नाटक

नागपुर. महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में एक चौकाने वाला सामने आया है, जहां एक शरुक्स ने अपने प्रेमिका के 4 वर्षीय बेटे को ट्रेन में लावारिस छोड़ दिया। बाद में अपहरण का नाटक रचा लेकिन जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पुलिस ने बच्चे को सकुशल मां के हवाले किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, पति को छोड़कर नागपुर आई एक महिला के युवक से प्रेम संबंध बन गए। युवक उसके साथ विवाह करने को तैयार था लेकिन उसके 4 वर्षीय बेटे को अपना नहीं चाहता था। जिसके चलते वह बच्चे को घर से ले गया और एक ट्रेन में लावारिस छोड़ दिया। पकड़ा गया आरोपी लाखनी, भंडारा निवासी हंसराज ज्ञानेश्वर दखने (25)



बताया गया। 30 वर्षीय पीड़िता ने कलह के चलते कुछ महीने पहले पति को छोड़ दिया और नागपुर आ गई। होटल में काम मिल गया और अपने 4 वर्ष के बच्चे के साथ गणेशपेट परिसर के एक लॉज में रहती है। वहीं उसकी पहचान हंसराज से हुई। दोनों के प्रेम संबंध बन गए और दोनों साथ रहने लगे। हंसराज ने उससे शादी करने के बारे में पूछा। पीड़िता ने बच्चे के साथ स्वीकार करने पर ही शादी करने की हामी दी। हंसराज उसके बच्चे को

स्वीकार नहीं करना चाहता था। शुक्रवार की दोपहर उसने पीड़िता से कहा कि वह बच्चे का एडमिशन एक स्कूल में करवाना चाहता है। बहाने से वह बालक को अपने साथ ले गया। शाम को लॉज में लौटा और महिला को बताया कि खापरी के स्वामी विवेकानंद अस्पताल के पास 3 लोगों ने बच्चे का अपहरण कर लिया जिनमें से 1 व्यक्ति को बच्चा पप्पा कह रहा था। महिला ने अपने पति को फोन लगाया। उसने बच्चे को साथ ले जाने की बात से इनकार कर दिया। महिला ने गणेशपेट थाने में बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गणेशपेट पुलिस के साथ मानव तस्करी विरोधी दस्ता भी काम पर लग गया। पुलिस ने हंसराज से कड़ी पूछताछ की। वह बार-बार अपना बयान बदल रहा था।

ओडिशा से गांजा का बड़ा जखीरा जब्त



मुंबई : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ओडिशा राज्य से गांजा की तस्करी कर रहे चार लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के पास से 111 किलो गांजा जब्त किया गया और इसकी कीमत 2 करोड़ रुपये है। एनसीबी ने तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई दो गाड़ियों को भी जब्त किया है। आशंका है कि इस मामले में अन्य आरोपी भी शामिल हैं और एनसीबी इसकी जांच कर रही है। एनसीबी को सूचना मिली थी कि ओडिशा राज्य से महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में गांजा की तस्करी की जा रही है। उस जानकारी के आधार पर एनसीबी ने तस्करी की गतिविधियों पर नजर रखी थी।